



arihant
समसामयिकी महासागर

₹145

सभी राष्ट्रीय
व राज्य स्तरीय
परीक्षाओं के
लिए उपयोगी

करेंट अफेयर्स अर्द्धवार्षिकी 2024

जनवरी 2024 से अब तक
का सम्पूर्ण कवरेज

मोदी 3.0

केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल 2024



राजनाथ सिंह
रक्षा



अमित शाह
मुख्य मन्त्री



नितिन गडकरी
राष्ट्रीय परिवहन



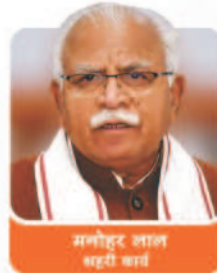
जगत प्रकाश यदु
स्वास्थ्य



शिवराज सिंह बोहरा
कृषि



निर्मला सीतारमण
वित्त



मनोहर लाल
खट्टर कार्य



पीयूष गोयल
वणिज्य और उद्योग



प्रेम सिंह तमांग
(सिक्किम)



चन्द्रबाबू नायडू
(आन्ध्र प्रदेश)



मोहन मांझी
(ओडिशा)

ओडिशा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और
आन्ध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव

करेंट अफेयर्स अर्द्धवार्षिकी 2024

जनवरी 2024 से अब तक
का सम्पूर्ण कवरेज

₹99 का Online Test पैकेज फ्री

करेंट अफेयर्स
(Jan-June 24)

50

Total Tests

Attempt Test

View

Price

₹99

Validity

6 Months

Coupon Code: **EwAACH**

पैकेज की विशेषताएँ

- ✓ Detailed Analysis रिपोर्ट
- ✓ Mock Test को Multiple Times Attempt (Re-Attempt) कर सकते हैं
- ✓ सभी प्रश्नों के Detailed Solutions भी

Login हेतु निर्देश



- www.examwitharihant.com पर Login करना होगा।
- इसके बाद Book Code/Coupon Code पर Click कर दिया गया Code डालना होगा।

Download App



अन्दर के पृष्ठों में

- ❖ लोकसभा चुनाव 2024 3-8
- ❖ राष्ट्रीय परिदृश्य 9-37
 - योजना/कार्यक्रम
 - सम्मेलन/बैठक
 - शिक्षा क्षेत्र
 - ऐप्प/पोर्टल 2024
 - रेलवे क्षेत्र
 - सूचकांक/रिपोर्ट 2024
 - कला एवं संस्कृति
 - महत्वपूर्ण विधेयक 2024
 - रिविज़न Boosters
 - Exam शूटर्स
- ❖ विश्व परिदृश्य 38-60
 - नव-नियुक्त प्रधानमन्त्री 2024
 - नव-निर्वाचित राष्ट्रपति 2024
 - सूचकांक/रिपोर्ट/रैंकिंग 2024
 - रिविज़न Boosters
 - Exam शूटर्स
- ❖ भारत एवं विश्व 61-69
 - रिविज़न Bullets
 - Exam शूटर्स
- ❖ अर्थव्यवस्था एवं बैंकिंग 70-89
 - RBI घटनाक्रम
 - बैंकिंग क्षेत्र
 - कॉर्पोरेट क्षेत्र
 - सम्मेलन/बैठक
 - सूचकांक/रिपोर्ट/रैंकिंग 2024
 - रिविज़न Boosters
 - Exam शूटर्स
- ❖ राज्य परिदृश्य 90-112
 - रिविज़न Boosters
 - Exam शूटर्स
- ❖ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 113-121
 - कम्प्यूटर/संचार प्रौद्योगिकी
 - रिविज़न Boosters
 - Exam शूटर्स
- ❖ अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी 122-128
 - ISRO गतिविधियाँ
 - NASA घटनाक्रम
 - रिविज़न Boosters
 - Exam शूटर्स
- ❖ रक्षा एवं प्रतिरक्षा 129-139
 - मिसाइल परीक्षण
 - सेवा में शामिल/सेवा मुक्ति
 - सैन्य अभ्यास
 - रिविज़न Boosters
 - Exam शूटर्स
- ❖ स्वास्थ्य एवं पोषण 140-144
 - रिविज़न Boosters
 - Exam शूटर्स
- ❖ कृषि, पर्यावरण एवं जैव-विविधता 145-150
 - रिविज़न Boosters
 - Exam शूटर्स
- ❖ खेल पैनोरमा 151-163
 - खेल समाचार
 - रिविज़न Boosters
 - Exam शूटर्स
- ❖ पुरस्कार एवं सम्मान 164-180
 - राष्ट्रीय (फिल्म व संगीत, साहित्य, आर्थिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, खेल विविध)
 - अन्तर्राष्ट्रीय (फिल्म व संगीत, साहित्य, आर्थिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, खेल विविध)
 - रिविज़न Boosters
 - Exam शूटर्स
- ❖ न्यूज लाइन 181-206
 - राष्ट्रीय (फिल्म व संगीत, साहित्य, आर्थिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, खेल विविध)
 - अन्तर्राष्ट्रीय (फिल्म व संगीत, साहित्य, आर्थिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, खेल विविध)
 - पुस्तक एवं लेखक
 - रिविज़न Boosters
 - Exam शूटर्स
- ❖ कौन क्या है 207-208

प्रकाशक : पायल जैन
चेयरमैन : वाई.सी.जैन

सम्पादक : संजय सागर
पब्लिशिंग मैनेजर : अमित वर्मा
प्रोजेक्ट मैनेजर : अमित त्यागी
कवर एवं लेआउट : बिलाल हाशमी
मुख्य पेज डिजाइनर : प्रदीप कुमार, हारून खान
टाइप सैटिंग : नितिन कुमार, हिमांशु

वितरण एवं विज्ञापन

जनरल मैनेजर : अनिल कुमार गुप्ता (9258074261)
ई-मेल : arihantmedia.anil@gmail.com
सेल्स एक्जीक्यूटिव : 9258332426

खालिद अन्जुम 9258076307
(बिहार, झारखण्ड एवं छत्तीसगढ़)
वितरण (Circulation) : 9258074261

कार्यालय

प्रधान कार्यालय : अरिहन्त मीडिया प्रोमोटर्स, कालिन्दी,
टीपी नगर, मेरठ, फोन : 0121-2401479, 2512970
फैक्स : 0121-2401648
वितरण/व्यावसायिक कार्यालय
अरिहन्त मीडिया प्रोमोटर्स 4577/15, अग्रवाल रोड,
दरियागंज, नई दिल्ली-2
फोन 011-23272342
इन्क्वायरी 0121-4030840
ई-मेल : arihantmedia.amit@gmail.com
वेबसाइट : www.arihantbooks.com

© प्रकाशक

अरिहन्त मीडिया प्रोमोटर्स के लिए श्रीमती पायल जैन द्वारा
प्रकाशित एवं मुद्रित अरिहन्त पब्लिकेशन्स (इण्डिया) लिमिटेड,
मेरठ से मुद्रित

इस पत्रिका में प्रकाशित सभी लेख उनके रचनाकारों के स्वयं के हैं,
तथा वे किसी भी स्थिति में उनसे सम्बन्धित सरकारी या
गैर-सरकारी संस्था या करेंट अफेयर्स.com सम्पादक मण्डल
के विचार नहीं हैं।

इस पत्रिका में प्रकाशित सूचनाएँ, समाचार, ज्ञान एवं तथ्य पूरी
तरह से सत्यापित किए गए हैं। यदि कोई जानकारी या तथ्य
गलत प्रकाशित हो गया है तो प्रकाशक, सम्पादक या मुद्रक उससे
किसी व्यक्ति-विशेष को पहुँची क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं हैं।

किसी भी स्थिति में न्यायिक क्षेत्र मेरठ (उत्तर प्रदेश) होगा।

करेंट अफेयर्स के नियमित अपडेट्स के लिए, हमें फॉलो करें ▶ Examwitharihant

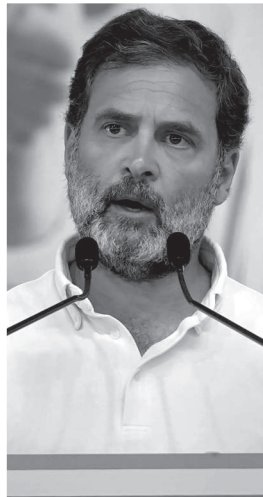
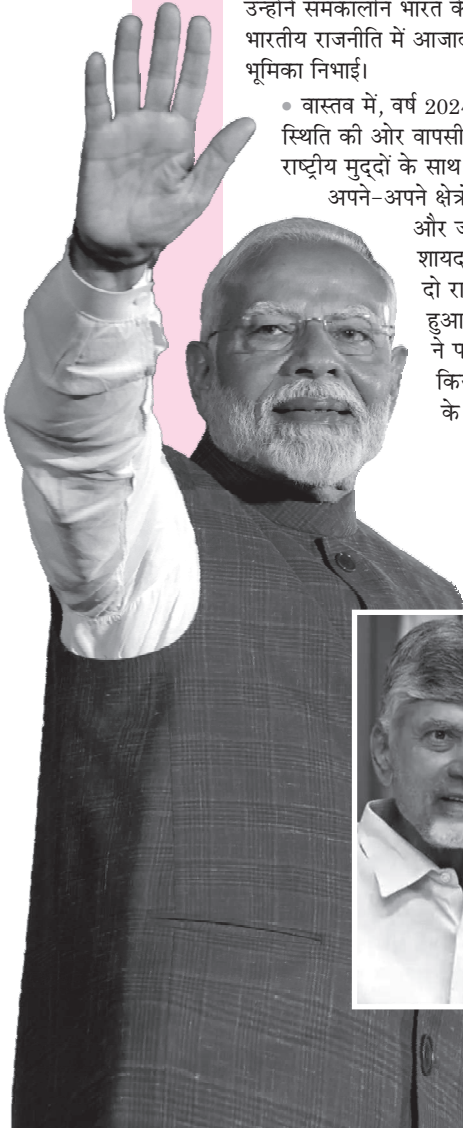
लोकसभा चुनाव 2024

नरेन्द्र मोदी का प्रधानमंत्री के रूप में तीसरा कार्यकाल

- BJP को 240 सीटें और कांग्रेस को 99 सीटें मिलने के साथ, भारत के चुनाव आयोग ने 543 लोकसभा क्षेत्रों में से 542 के परिणाम जारी कर दिए हैं।
- BJP की जीत का आंकड़ा वर्ष 2014 में जीती गई 282 सीटों और वर्ष 2019 में जीती गई 303 सीटों से काफी कम है।
- इसके विपरीत, कांग्रेस ने उल्लेखनीय वृद्धि की, और वर्ष 2019 में 52 तथा वर्ष 2014 में 44 के मुकाबले 99 सीटें हासिल कीं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अन्य कैबिनेट मंत्रियों ने 9 जून, 2024 को शपथ ग्रहण की।
- प्रधानमंत्री मोदी तीसरे कार्यकाल (मोदी 3.0) के लिए गठबन्धन सरकार का नेतृत्व करेंगे। वह जवाहरलाल नेहरू के बाद केवल दूसरे प्रधानमंत्री हैं जो लगातार तीसरी बार चुने गए हैं।
- भारत के सबसे लम्बे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले जवाहरलाल नेहरू थे। अपने 16 वर्ष से ज्यादा के शासनकाल में उन्होंने समकालीन भारत के लिए रूपरेखा तैयार की। उन्होंने भारतीय राजनीति में आजादी से पहले और बाद में भी अहम भूमिका निभाई।
- वास्तव में, वर्ष 2024 भारतीय राजनीति की पुरानी सामान्य स्थिति की ओर वापसी का प्रतीक है, जिसमें स्थानीय सरोकार राष्ट्रीय मुद्दों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, क्षेत्रीय क्षत्रप अपने-अपने क्षेत्रों में चुनावों को प्रभावित कर सकते हैं, और जाति एवं समुदाय के मध्य तालमेल शायद ही कभी मजबूत हो पाता है, यह सब दो राष्ट्रीय लहर वाले चुनावों के बाद हुआ है, जिसमें वर्ष 2014 में BJP ने पहली बार एकल-दलीय बहुमत हासिल किया और वर्ष 2019 में अपने अब तक के सर्वश्रेष्ठ परिणाम हासिल किए।

प्रमुख तथ्य

- पुनरुत्थानशील विपक्षी गठबन्धन ने स्थानीय अशांति और संविधान के भविष्य की चिन्ताओं का फायदा उठाते हुए भारत के 3 सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन करके प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अप्रत्याशित झटका दिया।
- परिणामस्वरूप, राष्ट्रीय जनतान्त्रिक गठबन्धन (NDA) को लोकसभा चुनावों में बहुत कम अन्तर से बहुमत प्राप्त हुआ।
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार जीतने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बने। NDA के पास 543 में से 293 सीटें हैं।
- उत्तरी भारत में कांग्रेस की आश्चर्यजनक वापसी, तथा सहयोगी समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के शानदार प्रदर्शन, जिसने BJP को पीछे रखने में मदद की, ने **इण्डियन नेशनल डेवलपमेंटल इक्वलिसिटी अलायन्स (INDIA)** को, जिसे एंजित पोल में खारिज कर दिया गया था, क्रमशः पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में 233 सीटें जीतने में मदद की, जबकि क्षेत्रीय दिग्गज शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में अपनी-अपनी पार्टियों के भीतर अपने प्रतिद्वन्द्वियों को परास्त कर दिया।
- इन दोनों ने मिलकर NDA की वर्ष 2019 की कुल सीटों में से लगभग 60 सीटें कम कर दीं। दक्षिण में आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में BJP सरकार की आश्चर्यजनक और अप्रत्याशित जीत के विपरीत, हिन्दी भाषी क्षेत्रों में नरेन्द्र मोदी की उम्मीदों के मुकाबले खराब प्रदर्शन हुआ और सीटें हारी।
- इसके अतिरिक्त, असम, छत्तीसगढ़ और अरुणाचल प्रदेश में भी BJP को बहुमत मिला। सूरत सीट पर BJP ने बिना किसी विरोध के जीत हासिल की।
- इस जनादेश के कारण सत्तारूढ़ पार्टी को हाल के भौगोलिक क्षेत्रों में लाभ मिला है, जहां वह कमजोर थी, जबकि उसे उन क्षेत्रों में सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ा है जहां वह मजबूत थी।



शपथ ग्रहण समारोह में विदेशी मेहमान

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में सात देशों के गणमान्य व्यक्ति (शासनाध्यक्ष/राष्ट्राध्यक्ष) शामिल हुए, जो निम्न हैं।



- रानिल विक्रमसिंघे (राष्ट्रपति, श्रीलंका)
- डॉ. मोहम्मद मुइज्जु (राष्ट्रपति, मालदीव्स)
- अहमद अफीफ (उप-राष्ट्रपति, सेशेल्स)
- शेख हसीना (प्रधानमंत्री, बांग्लादेश)
- प्रविन्द कुमार जगन्नाथ (प्रधानमंत्री, मॉरिशस)
- पुरुष कमल दहल 'प्रचण्ड' (प्रधानमंत्री, नेपाल)
- त्थोरिंग तोबगे (प्रधानमंत्री, भूटान)

सबसे बड़े विजेता

नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कांग्रेस के अजय राय को हराकर रिकॉर्ड तीसरी बार वाराणसी सीट जीती। मोदी ने 612970 वोट (54.24%) के साथ अजय राय को [460457 वोट (40.74%)] से हराया। लेकिन इस उपलब्धि के साथ कुछ नाराजगी भी थी क्योंकि वर्ष 2019 की तुलना में मोदी का हिस्सा लगभग 9% कम हो गया। यह देखते हुए कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भारत की 543 लोकसभा सीटों में से वाराणसी का प्रतिनिधित्व करते हैं, यह सबसे प्रसिद्ध निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। वर्ष 1991 से, यह निर्वाचन क्षेत्र भगवा पार्टी का गढ़ रहा है, और वर्ष 2014 से प्रधानमंत्री मोदी इस सीट पर काबिज हैं।

अखिलेश यादव

ऐसा लग रहा था कि BJP उत्तर प्रदेश में लगातार दो चुनाव जीतेगी। आम सहमति यह थी कि राम मन्दिर के उद्घाटन के कारण BJP वर्ष 2019 के अपने कुल वोटों के बराबर या उससे आगे निकल जाएगी।

अन्तिम परिणाम बताते हैं कि BJP और सपा पहले स्थान पर बराबरी पर हैं। भारतीय राजनीति का नारा हमेशा से यही रहा है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, और अखिलेश यादव और सपा ने निस्संदेह NDA-3 की यात्रा को और अधिक उथल-पुथल भरा बना दिया।

अमित शाह

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने निकटतम कांग्रेस प्रतिद्वन्द्वी सोनल रमनभाई पटेल पर सात लाख से ज्यादा वोटों की बढ़त के साथ गुजरात के गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में जबरदस्त जीत हासिल की।

चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक शाह को कुल 1010972 वोट मिले, जबकि पटेल को 266256 वोट मिले। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में अमितशाह ने लगभग 5.57 लाख वोटों के साथ कांग्रेस पार्टी के चतुर सिंह जवानजी चावड़ा को हराकर इस सीट पर जीत दर्ज की थी।

राजनाथ सिंह

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश की लखनऊ सीट पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रविदास मेहरोत्रा को 1.35 लाख से ज्यादा वोटों से हराया। मेहरोत्रा को 477550 वोट मिले, जबकि राजनाथ सिंह को 612709 वोट मिले। दोनों के मध्य 135159 वोटों का अन्तर था। वर्ष 2019 के चुनाव में राजनाथ सिंह ने शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा को 3.5 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था।

राहुल गांधी

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वास्तविक नेता राहुल गाँधी को लम्बे समय से आलोचना और अवमानना का सामना करना पड़ रहा है। वर्ष 2024 के चुनाव में राहुल गाँधी ने वायनाड सीट पर 3.64 लाख वोटों के अन्तर से जीत दर्ज की। उन्होंने रायबरेली सीट पर भी 687649 वोटों से जीत दर्ज की।

सबसे बड़ी जीत

उम्मीदवार	दल	चुनाव क्षेत्र	जीत का अन्तर	कुल वोट
सुप्रिया सुले	NCP-SCP	बारामती, महाराष्ट्र	151465	714290
नितिन गडकरी	BJP	नागपुर, महाराष्ट्र	137603	655027
ज्योतिरादित्य सिंधिया	BJP	गुना, मध्य प्रदेश	540929	923302
रोडमल नागर	BJP	राजगढ़, मध्य प्रदेश	146089	758743
शिवराज सिंह चौहान	BJP	विदिशा, मध्य प्रदेश	821408	1116460
मितेश पटेल	BJP	आनन्द गुजरात	89939	612484
डिम्पल यादव	SP	मैनपुरी, उत्तर प्रदेश	221639	598526
अभिषेक बनर्जी	TMC	डायमण्ड हार्बर, पश्चिम बंगाल	710930	1048230
अमृत पाल सिंह	निर्दलीय	खडूर साहिब	197120	404430

सबसे बड़ी हार

स्मृति ईरानी

चुनाव 2019 में राहुल गाँधी को हराकर लोकसभा के लिए चुनी गई BJP की स्मृति ईरानी को करारी हार का सामना करना पड़ा। स्मृति ईरानी कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा से 1.6 लाख वोटों से हार गई।

विक्रमादित्य सिंह

कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह कंगना रनौत से हार गए, जिन्होंने इस चुनावी मौसम में BJP के टिकट पर अपनी शुरुआत की। हिमाचल की इस सीट पर वोटों का अन्तर 74000 से अधिक था। विक्रमादित्य सिंह हिमाचल प्रदेश के छह बार मुख्यमंत्री रहे दिवंगत वीरभद्र सिंह और मौजूदा सांसद प्रतिभा सिंह के बेटे हैं।

राजीव चन्द्रशेखर

केरल के तिरुवनन्तपुरम में केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चन्द्रशेखर को कांग्रेस के दिग्गज नेता शशि थरूर ने 16077 से अधिक मतों के अन्तर से हराया।

अर्जुन मुण्डा

झारखण्ड के खूण्टी लोकसभा क्षेत्र में केन्द्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री और मौजूदा सांसद अर्जुन मुण्डा को कांग्रेस के काली चरण मुण्डा से 1.4 लाख मतों के अन्तर से हार का सामना करना पड़ा।

हारने वाले बड़े नेता

उम्मीदवार	दल	चुनाव क्षेत्र	मतों से हार	कुल मत
अरूप पटनायक	BJD	पुरी, ओडिशा	104709	524621
उमर अब्दुल्ला	NC	बारामुल्ला, जम्मू और कश्मीर	145214	268339
महबूबा मुफ्ती	PDP	अनन्तनाग-राजौरी (जण्ड के)	281794	240042
मेनका गांधी	BJP	सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश	43174	401156
नकुल कमलनाथ	कांग्रेस	छिन्दवाड़ा, मध्य प्रदेश	113618	531120
भूपेश बघेल	कांग्रेस	राजनान्द गाँव, छत्तीसगढ़	44411	667646

लोकसभा चुनाव में जीतने वाले प्रसिद्ध व्यक्ति

- हेमा मालिनी (BJP) ने उत्तर प्रदेश के मथुरा निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की।
- शत्रुघ्न सिन्हा (TMC), पश्चिम बंगाल के आसनसोल निर्वाचन क्षेत्र से जीते
- यूसुफ पठान (TMC), पश्चिम बंगाल की बहरामपुर सीट से विजयी
- सुरेश गोपी (BJP) ने केरल के त्रिशूर निर्वाचन क्षेत्र जीता।
- मनोज तिवारी (BJP), उत्तर पूर्वी दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से विजयी हुए।

पहली बार युवा संसदीय सदस्य

- उत्तर प्रदेश की कौशाम्बी सीट से समाजवादी पार्टी के पुष्पेन्द्र सरोज विजयी हुए।
- समाजवादी पार्टी से जुड़ी प्रिया सरोज ने उत्तर प्रदेश के मछलीशहर निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की।
- राजस्थान की भरतपुर सीट पर BJP की संजना जाटव विजयी रहीं।

- बिहार के समस्तीपुर निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस की शाम्भवी चौधरी विजयी रहीं।

वर्ष 2024 में लोकसभा में विभिन्न राजनीतिक दलों की स्थिति

राजनीतिक दल	सीटें	वोट शेयर
भारतीय जनता पार्टी (BJP)	240	36.56%
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC)	99	21.19%
समाजवादी पार्टी (SP)	37	4.58%
अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (AITC)	29	4.37%
द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK)	22	1.82%
तेलुगु देशम (TDP)	16	1.98%
जनता दल (यूनाइटेड) (JD(U))	12	1.25%
शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) (SHSUBT)	9	1.48%
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरदचन्द्र पवार (NCPSP)	8	0.92%
शिवसेना (SHS)	7	1.15%
युवजन श्रमिका रायथु कांग्रेस पार्टी (YSRCP)	4	2.06%
राष्ट्रीय जनता दल (RJD)	4	1.57%
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (CPI(M))	4	1.76%
इण्डियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML)	3	0.27%
आम आदमी पार्टी (AAP)	3	1.11%
झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM)	3	0.41%
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) (लिबरेशन) (CPI(ML)(L))	2	0.27%
जनता दल (सेक्युलर) (JD(S))	2	0.34%
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI)	2	0.49%
जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस (JKN)	2	0.18%
यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी, लिबरल (UPPL)	1	0.08%
असम गण परिषद (AGP)	1	0.20%
केरल कांग्रेस (KEC)	1	0.04%
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP)	1	0.32%
जनता की आवाज पार्टी (VOTPP)	1	0.09%
शिरोमणि अकाली दल (SAD)	1	0.28%
राष्ट्रीय लोकतान्त्रिक पार्टी (RLTP)	1	0.09%
सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा (SKM)	1	0.03%
अपना दल (सोनीलाल) (ADAL)	1	0.13%
AJSUP पार्टी (AJSUP)	1	0.07%
ऑल इण्डिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM)	1	0.22%

महिला उम्मीदवार

- 18वीं लोकसभा में 74 महिला सांसद होंगी, जो वर्ष 2019 में निर्वाचित 78 महिला सांसदों की संख्या से थोड़ी कम है।
- भारतीय चुनाव आयोग (ECI) के आंकड़ों से पता चलता है कि वर्ष 2024 में नई लोकसभा में महिलाओं की संख्या 13.6% होगी, जबकि वर्ष 2019 में निर्वाचित 17वीं लोकसभा के सभी सदस्यों में महिलाओं की संख्या 14.3% थी।

- वर्ष 2024 के आम चुनावों के 7 चरणों में कुल 797 महिलाएँ मैदान में उतरीं, जो 19 अप्रैल से 1 जून 2024 के मध्य हुए थे। महिला आरक्षण विधेयक, 2023 को लोकसभा में पेश किये जाने के बाद से अब तक कोई आम चुनाव नहीं हुआ है।
- यह विधेयक, जो अभी तक प्रभावी नहीं हुआ है, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का इरादा रखता है।
- लोकसभा चुनाव में BJP की हेमा मालिनी, TMC की महुआ मोइत्रा, NCP की सुले और सपा की डिम्पल यादव अपनी सीटों पर कायम रहीं, लेकिन कंगना। रनौत और मीसा भारती जैसे उम्मीदवारों की जीत ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा।
- जीतने वाली सबसे युवा उम्मीदवार समाजवादी पार्टी की 25 वर्षीय प्रिया सरोज थीं, जिन्होंने मछलीशहर से चुनाव लड़ा था और कैराना सीट से 29 वर्षीय इकरा चौधरी थीं।
- विशेष रूप से 50% उम्मीदवार महिला होने के कारण, नाम तमिलर काची जैसी पार्टियों ने समान लिंग प्रतिनिधित्व प्राप्त किया।
- राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), दोनों में 40% महिला उम्मीदवार थीं, ये 2 अन्य पार्टियाँ थीं, जिनमें महिलाओं की उपस्थिति उल्लेखनीय थी।
- जहाँ राष्ट्रीय जनता दल (RJD) में महिलाओं की भागीदारी 29% थी, वहीं झारखण्ड मुक्ति मोर्चा (JMM) और बीजू जनता दल (BJD) दोनों में 33% थी।
- 20% समाजवादी पार्टी को और 25% तृणमूल कांग्रेस (TMC) को मिले।
- कुल मिलाकर, विधान सभा चुनावों में 8360 उम्मीदवार मैदान में थे।
- चुनाव में भाग लेने वाले निर्दलीय उम्मीदवारों में तीन ट्रांसजेण्डर लोग थे। हालाँकि, वे सभी चुनाव हार गए। पहली और दूसरी लोकसभा में 24-24 महिला सांसद थीं।

विवादास्पद क्षण

- जिस चुनाव में विवाद न हो, उसका नीरस होना तथ्य है। वर्ष 2024 में 18वीं लोकसभा के चुनाव के दौरान भी ऐसी ही घटनाएँ हुईं, जब धार्मिक संघर्ष से लेकर किसान विरोध तक हर चीज ने चुनाव के नतीजों को प्रभावित किया।

धार्मिक विवाद

वर्ष 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले, नरेन्द्र मोदी ने एक विवादास्पद बयान दिया, जिसका बहुत से लोगों ने यह मतलब निकाला कि वह मुस्लिम आबादी को निशाना बना रहे हैं। राजस्थान के टोंक-सवाई माधोपुर, बिहार के मुंगेर, पश्चिम बंगाल के मालदा और उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में अपने चुनावी भाषणों में, उन्होंने मुसलमानों के मध्य धन के वितरण के बारे में अपना दावा दोहराया। इस भाषण से तथ्य-जांच और 'घृणास्पद भाषण' के विरुद्ध प्रतिक्रिया भड़क उठी; कुछ विदेशी मीडिया आउटलेट्स ने इसे 'देश के दूर-दराज लोगों के लिए मुस्लिम विरोधी कुत्ते की सीटी' के रूप में सन्दर्भित किया।

किसानों का विरोध प्रदर्शन

पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कृषि क्षेत्रों में BJP के खराब प्रदर्शन के लिए इन क्षेत्रों में बढ़ते असंतोष को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। यह पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में विशेष रूप से सच है, जो 3 मुख्य कृषि राज्य हैं। क्षेत्र में महत्वपूर्ण असफलताओं के कारण, सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) लोकसभा में बहुमत हासिल करने में असमर्थ रही है।

इन चुनाव परिणामों के बारे में लोगों की धारणा 9 अगस्त, 2020 से 20 दिसम्बर, 2021 तक राष्ट्रीय राजधानी के बाहरी इलाके में हुए ऐतिहासिक किसान प्रदर्शनों के बाद उपजे गुस्से से उपजी है।

आदर्श आचार संहिता

16 मार्च को लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। सभी दलों द्वारा स्वीकार किए जाने वाले और चुनाव के दौरान लागू किए जाने वाले रीति-रिवाजों के संग्रह को आदर्श आचार संहिता के रूप में जाना जाता है। इसका लक्ष्य सत्तारूढ़ दल को राज्य के संसाधनों या धन का दुरुपयोग करने से रोकना है, साथ ही चुनाव, मतदान और मतगणना प्रक्रियाओं की स्वच्छता, व्यवस्था और शान्ति बनाए रखना है। किसी भी कानूनी समर्थन की कमी के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार इसकी अखण्डता को बनाए रखा है। चुनाव आयोग के पास किसी भी आचार संहिता के उल्लंघन की जांच करने और दण्ड लगाने का पूरा अधिकार है।

लोकसभा चुनाव 2024 : रोचक तथ्य

- कांग्रेस ने 20 वर्ष पश्चात इलाहाबाद लोकसभा सीट पर फिर से कब्ज़ा जमाया। लोकसभा में 37 सीटों के साथ समाजवादी पार्टी अब संसद में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है और उसने अब तक का अपना सबसे अच्छा चुनाव जीता है।
- वर्ष 2024 में उत्तर प्रदेश में BJP को केवल 33 सीटें ही मिलेंगी। चूंकि वर्ष 2009 में वे केवल 10 सीटें ही हासिल कर पाए थे, इसलिए यह उनका सबसे खराब प्रदर्शन था।
- BJP के लल्लू सिंह फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में सपा के अवधेश प्रसाद से 50,000 से अधिक मतों से हार गए, जिसमें 6 जनवरी, 2024 को राम मन्दिर समारोह स्थल अयोध्या भी शामिल है।
- गुजरात में कांग्रेस ने वर्ष 2009 के बाद पहली बार लोकसभा सीट हासिल की। वर्ष 2014 और वर्ष 2019 में उसे एक भी सीट नहीं मिली थी।
- वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में 13 केन्द्रीय मन्त्री हारे हैं। इस लोकसभा चुनाव में सबसे बड़े अन्तर से शंकर लखवानी ने 11.72 लाख वोटों के अंतर से इन्दौर में NOTA को हराया।
- कांग्रेस उम्मीदवार ने चुनाव मैदान छोड़ दिया और BJP में शामिल हो गए। इन्दौर में NOTA को दो लाख से ज्यादा वोट पड़े।
- वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में, BJP को तमिलनाडु को छोड़कर भारत के हर राज्य में कम से कम एक लोकसभा सीट हासिल होगी।
- लगातार तीसरे लोकसभा चुनाव में BJP ने दिल्ली की सभी सातों सीटें जीतीं।
- कांग्रेस ने वर्ष 2009 में दिल्ली की सभी सातों सीटें जीतीं, जिससे यह एक विशेष राज्य बन गया। लगातार दो विधानसभा चुनाव जीतने के बावजूद, AAP यहाँ कभी जीत हासिल नहीं कर पाई। 25 वर्ष की आयु में, सपा के पुष्पेंद्र सरोज लोकसभा के सबसे युवा सदस्य हैं।
- 17वीं लोकसभा की औसत आयु 59 वर्ष थी, उसकी तुलना में 18वीं लोकसभा की औसत आयु 56 वर्ष है।
- आतंकवाद से जुड़े अपराधों में जेल में बन्द 2 लोगों को चुना गया है। अमृतपाल सिंह ने पंजाब में खडूर शाहिब को हराया।
- जम्मू-कश्मीर के बारामूला में शेख अब्दुल 'इंजीनियर' रशीद ने भी अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी को हराया।
- वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में सात निर्दलीय उम्मीदवार विजयी हुए। हालाँकि पंजाब विधानसभा चुनाव में AAP ने भारी 7 हासिल की, लेकिन उसे केवल 3 सीटें मिलीं।
- तमिलनाडु में NDA को 18.27% वोट मिले, हालाँकि वह एक भी सीट हासिल करने में असफल रही।
- केरल में BJP अपनी पहली सीट सुरक्षित करने में सफल रही। BJP 19 केन्द्रशासित प्रदेशों में से 12 सीटें सुरक्षित करने में सफल रही।

- कांग्रेस ने वर्ष 2009 में 206 सीटें जीतने के बाद से 99 की अपनी उच्चतम रेटिंग हासिल की। केरल वह राज्य था जहां कांग्रेस ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया, जहां उसने 14 सीटें जीतीं।
- INDIA गुट के लिए सर्वोच्च अंक उत्तर प्रदेश के लिए 43, महाराष्ट्र के लिए 30, पश्चिम बंगाल के लिए 39, तमिलनाडु के लिए 39, केरल के लिए 19 और पंजाब के लिए 10 थे।
- तृणमूल कांग्रेस (37.9%) वह पार्टी है जो सबसे अधिक महिलाओं को लोकसभा में भेजेगी। कंगना रनौत, अरुण गोविल, हेमा मालिनी, शत्रुघ्न सिन्हा, मनोज तिवारी, रवि किशन, सुरेश गोपी, दीपक 'देव' अधिकारी, रचना बनर्जी और जून माला उन अभिनेताओं में शामिल हैं, जो 18वीं लोकसभा में नजर आएंगे।
- वर्ष 2024 के चुनाव में, 1.05 मिलियन मतदान स्थलों पर 1.8 मिलियन VVPAT प्रणालियाँ और 1.7 मिलियन नियन्त्रण इकाइयाँ स्थापित की गईं। कुल 642 मिलियन मतदाताओं में से 312 मिलियन महिलाओं ने चुनाव में मतदान किया।

18वीं लोकसभा : महत्वपूर्ण तथ्य

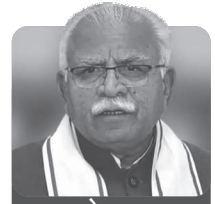
- 18वीं लोकसभा में करीब 280 सांसद पहली बार चुनकर आए हैं। 17वीं लोकसभा (2019) में 267 सदस्य पहली बार सांसद बने थे।
- कुल 263 नवनिर्वाचित सांसद पहले भी लोकसभा के सदस्य के रूप में कार्य कर चुके हैं।
- पुनः निर्वाचित सांसदों में से 8 ने अपना निर्वाचन क्षेत्र बदल दिया तथा एक को 2 निर्वाचन क्षेत्रों से पुनः निर्वाचित किया गया।
- 17वीं लोकसभा में पुनः निर्वाचित 9 सांसद एक अलग पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जबकि 8 अन्य सांसद उस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे जो अपनी पिछली पार्टी से अलग हुई थी।
- चुनाव लड़ने वाले 53 मंत्रियों में से 35 विजयी हुए हैं।
- 4 'पुराने' योद्धाओं (पीयूष गोयल, अनिल देसाई, शाहू छत्रपति और किरसन नामदेव) ने इस वर्ष अपना पहला लोकसभा चुनाव जीता है। जबकि 3 वरिष्ठ नागरिक हैं।
- कोडिकुनिल सुरेश (केरल के मावेलिककारा से कांग्रेस सांसद) सातवीं बार लोकसभा के लिए चुने गए हैं।
- 18वीं लोकसभा में सांसदों की औसत आयु 56 वर्ष है। केवल 11% सांसद 40 वर्ष या उससे कम आयु के हैं।
- 18वीं लोकसभा में 5% सांसदों के पास डॉक्टरेट की डिग्री है। इनमें 3 महिला सांसद भी हैं। 18वीं लोकसभा में 7% सांसद वकील हैं। 4% मेडिकल प्रैक्टीशनर हैं।
- नवनिर्वाचित सांसदों में से 78% ने स्नातक शिक्षा पूरी कर ली है।
- 14% सांसद महिलाएं हैं, वर्ष 2019 से कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं।
- 41 पार्टियों के उम्मीदवार चुने गए हैं। वर्ष 2019 में, लोकसभा में 36 पार्टियों का प्रतिनिधित्व था।
- राष्ट्रीय दलों ने 346 सीटें (64%) जीती हैं। कम से कम एक राज्य में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त दलों ने 179 सीटें (33%) जीती हैं।
- 18वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित सांसदों के बीच कृषि और सामाजिक कार्य सबसे आम पेशे हैं।
- उत्तर प्रदेश में अभिनेता अरुण गोविल (मेरठ), कांग्रेस नेता किशोरी लाल शर्मा (अमेठी) और चन्द्रशेखर आजाद (नगीना) सहित 45 सांसद पहली बार सदस्य चुने गए।

मोदी 3.0

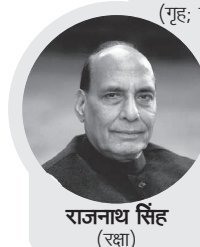
मन्त्री और पोर्टफोलियो



अमित शाह
(गृह; सहकारिता)



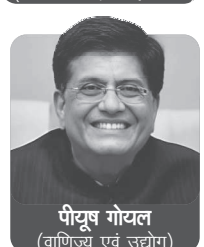
मनोहर लाल
(आवासन एवं शहरी कार्य)



राजनाथ सिंह
(रक्षा)



शिवराज सिंह चौहान
(कृषि एवं ग्रामीण विकास)



पीयूष गोयल
(वाणिज्य एवं उद्योग)

केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल

श्री नरेन्द्र मोदी

प्रधानमन्त्री तथा निम्न मन्त्रालयों के प्रभारी: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मन्त्रालय; परमाणु ऊर्जा विभाग; अन्तरिक्ष विभाग; सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे; और अन्य सभी विभाग, जो किसी मन्त्री को आवंटित नहीं किए गए हैं।

कैबिनेट मन्त्री

राजनाथ सिंह	रक्षा
अमित शाह	गृह; सहकारिता
नितिन जयराम गडकरी	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग
जगत प्रकाश नड्डा	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण; रसायन एवं उर्वरक
शिवराज सिंह चौहान	कृषि एवं किसान कल्याण; ग्रामीण विकास
श्रीमती निर्मला सीतारमण	वित्त; कॉर्पोरेट कार्य
डॉ. सुब्रह्मण्यम जयशंकर	विदेश
मनोहर लाल	आवासन एवं शहरी कार्य; ऊर्जा
एचडी कुमारस्वामी	भारी उद्योग; इस्पात
पीयूष गोयल	वाणिज्य एवं उद्योग
धर्मेन्द्र प्रधान	शिक्षा
जीतन राम मांझी	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम
राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह	पंचायती राज; मत्स्य पालन, पशुपालन डेयरी
सर्बानन्द सोनोवाल	पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग
डॉ. वीरेन्द्र कुमार	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता

किंजरापु राममोहन नायडू	नागर विमानन
प्रल्हाद जोशी	उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण; नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा
जुएल ओराम	जनजातीय कार्य
गिरिराज सिंह	वस्त्र
अश्विनी वैष्णव	रेल; सूचना एवं प्रसारण; इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी
ज्योतिरादित्य एम सिन्धिया	संचार; पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास
भूपेन्द्र यादव	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन
गजेन्द्र सिंह शेखावत	संस्कृति; पर्यटन
श्रीमती अन्नपूर्णा देवी	महिला एवं बाल विकास
किरेन रिजिजू	संसदीय कार्य; अल्पसंख्यक कार्य
हरदीप सिंह पुरी	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस
डॉ. मनसुख मण्डाविया	श्रम एवं रोजगार; युवा कार्यक्रम एवं खेल
जी. किशन रेड्डी	कोयला मंत्री; खान
चिराग पासवान	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग
सीआर पाटिल	जल शक्ति

राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार)

राव इन्द्रजीत सिंह	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन (स्वतन्त्र प्रभार); योजना (स्वतन्त्र प्रभार); संस्कृति
डॉ. जितेन्द्र सिंह	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (स्वतन्त्र प्रभार); पृथ्वी विज्ञान (स्वतन्त्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय; कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन; परमाणु ऊर्जा विभाग; अन्तरिक्ष विभाग
अर्जुन राम मेघवाल	विधि एवं न्याय (स्वतन्त्र प्रभार); संसदीय कार्य
जाधव प्रतापराव गणपतराव	आयुष (स्वतन्त्र प्रभार); स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
जयन्त चौधरी	कौशल विकास और उद्यमिता (स्वतन्त्र प्रभार); शिक्षा

राज्य मंत्री

जितिन प्रसाद	वाणिज्य एवं उद्योग; इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी
श्रीपद येसो नाइक	विद्युत; नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा
पंकज चौधरी	वित्त
कृष्ण पाल	सहकारिता
रामदास अठावले	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
रामनाथ ठाकुर	कृषि एवं किसान कल्याण

नित्यानन्द राय	गृह
अनुप्रिया पटेल	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण; रसायन एवं उर्वरक
वी. सोमन्ना	जल शक्ति; रेलवे
डॉ. चन्द्र शेखर पेम्मासानी	ग्रामीण विकास; संचार
एसपी सिंह बघेल	मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी; पंचायती राज
सुश्री शोभा करंदलाजे	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम; श्रम एवं रोजगार
कीर्तिवर्धन सिंह	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन; विदेश
बीएल वर्मा	उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण; सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
शान्तनु ठाकुर	पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग
सुरेश गोपी	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस; पर्यटन
डॉ. एल. मुरुगन	सूचना एवं प्रसारण; संसदीय कार्य
अजय टम्टा	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग
बंदी संजय कुमार	गृह
कमलेश पासवान	ग्रामीण विकास
भागीरथ चौधरी	कृषि एवं किसान कल्याण
सतीश चन्द्र दुबे	कोयला; खान
संजय सेठ	रक्षा
रवनीत सिंह	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग; रेलवे
दुर्गादास उइके	जनजातीय कार्य
श्रीमती रक्षा निखिल खडसे	युवा कार्यक्रम एवं खेल
सुकान्त मजूमदार	शिक्षा; उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास
श्रीमती सावित्री ठाकुर	महिला एवं बाल विकास
तोखन साहू	आवासन एवं शहरी कार्य
राज भूषण चौधरी	जल शक्ति
भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा	भारी उद्योग; इस्पात
हर्ष मल्होत्रा	कॉर्पोरेट कार्य; सड़क परिवहन एवं राजमार्ग
श्रीमती निमुबेन जयन्तीभाई बांभणिया	उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण
मुरलीधर मोहोल	सहकारिता; नागर विमानन
जॉर्ज कुरियन	अल्पसंख्यक कार्य; मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी
पबित्र मार्गेरिता	विदेश; वस्त्र

राष्ट्रीय परिदृश्य



CPGRAMS- SMART सरकार के लिए एक आधार

- प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (DARPG) को 3 जून, 2024 को वाशिंगटन DC स्थित IBM सेक्टर फॉर बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अमेरिकी सरकार के कर्मियों और अन्य हितधारकों से बात करने के लिए कहा।
- प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (DARPG) के सचिव श्री वी श्रीनिवास ने केन्द्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) पर भारतीय प्रस्तुति दी।
- यह समझना कि प्रौद्योगिकी किस प्रकार लोगों को सशक्त बना सकती है, जनता और सरकार के मध्य की दूरी को कम कर सकती है, तथा जवाबदेही और पारदर्शिता को अधिकतम कर सकती है।
- CPGRAMS के 10-चरणीय सुधारों को व्यवहार में लाया गया है, जिससे शिकायत निवारण की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, लेकिन शिकायत निवारण की समयबद्धता में कमी आई है।
- भारत ने प्रत्येक माह 1.02 लाख मुद्दों का मानचित्रण किया है और 1.5 लाख से अधिक शिकायतों का सफलतापूर्वक समाधान किया है।

नेशनल बुक ट्रस्ट का स्कूल शिक्षा विभाग के साथ समझौता ज्ञापन

- नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मन्त्रालय के, तत्वावधान में, स्कूल शिक्षा विभाग, शिक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार और नेशनल बुक ट्रस्ट ने 3 जून, 2024 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- राष्ट्रीय ई- पुस्तकालय डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म की संस्थागत नींव स्थापित करने के लिए इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
- राष्ट्रीय ई- पुस्तकालय, जो अपनी तरह का पहला डिजिटल पुस्तकालय है, का लक्ष्य भारतीय बच्चों और युवाओं में पढ़ने के प्रति आजीवन प्रेम को प्रोत्साहित करना है, तथा इसके लिए उन्हें अंग्रेजी को छोड़कर 22 से अधिक भाषाओं में 40 से अधिक प्रतिष्ठित प्रकाशकों द्वारा लिखी गई 1000 से अधिक गैर-शैक्षणिक पुस्तकें उपलब्ध कराना है।
- इसका लक्ष्य भूगोल, भाषा, शैली और पढ़ने के स्तर के संदर्भ में उच्च गुणवत्ता वाली पुस्तकों को अधिक व्यापक रूप से उपलब्ध कराना, और साथ ही देश में बच्चों एवं किशोरों को डिवाइस-स्वतन्त्र पहुँच प्रदान करना शामिल होगा।

केन्द्र सरकार द्वारा नई मोबाइल नम्बर सीरीज की शुरुआत

- केन्द्र सरकार ने 3 जून 2024 को सेवा या लेन-देन सम्बन्धी कॉलों के लिए एक नई नम्बरिंग श्रृंखला, 160xxxxxxx, शुरू की।
- इस कार्रवाई का उद्देश्य 10 अंकों वाले मोबाइल नम्बरों का उपयोग करने वाले टेलीमार्केटर्स से आने वाली अवांछित वॉयस कॉल को कम करना तथा वैध कॉलों की शीघ्र पहचान करने में नागरिकों सहायता करना है।
- टेलीमार्केटर्स को लेन-देन, सेवा और प्रचार सम्बन्धी कॉलों के लिए 140xxxxxxx श्रृंखला सौंपी गई है।
- हालाँकि, उपभोक्ता अक्सर इन कॉलों को नजर-अन्दाज कर देते हैं, क्योंकि इनका उपयोग अक्सर प्रचार उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जिसके कारण वे महत्वपूर्ण सेवा और लेन-देन सम्बन्धी सम्पर्कों से चूक जाते हैं।
- दूरसंचार विभाग ने घोषणा की है कि प्रमुख संस्थाएँ केवल नई 160xxxxxxx श्रृंखला पर ही सेवा और लेन-देन सम्बन्धी कॉल करेंगी।
- वैध और विज्ञापन कॉल के मध्य अन्तर करने से नागरिकों को अपने संचार को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबन्धित करने में सहायता मिलेगी।

- दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (TSPs) को 160 शृंखला से नम्बर आवण्टित करने से पहले प्रत्येक इकाई का व्यापक सत्यापन सुनिश्चित करना होगा।

लिंग संवेदनशीलता समिति का पुनर्गठन

- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 1 जून, 2024 को अपनी लिंग संवेदनशीलता और आंतरिक शिकायत समिति (GSICC) संरचना में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया।
- यह कार्रवाई यौन उत्पीड़न और लिंग संवेदनशीलता के विरुद्ध वर्ष 2013 के कानून का अनुपालन करती है। यह इस बात पर बल देता है कि न्यायालय लिंग से जुड़े मुद्दों से निपटती रहेगी।
- पुनर्गठन की प्रक्रिया का नेतृत्व भारत के मुख्य न्यायाधीश ने किया, जिन्होंने न्यायमूर्ति हिमा कोहली को अध्यक्ष नियुक्त किया।
- डॉ. सुखदा प्रीतम को सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है, जबकि न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना को सदस्य के रूप में चुना गया है।
- यह संगठन अधिक प्रभावी है, क्योंकि इसके नेतृत्व ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि इसमें कानूनी और बौद्धिक विशेषज्ञता का संयोजन हो।
- यह व्यवस्थित दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि समिति एक समेकित इकाई के रूप में कार्य करती रहे।

5G इमरजेंसी कनेक्टिविटी के लिए ड्रोन बैलून का परीक्षण

- दूरसंचार विभाग (DoT) 1 जून, 2024 को दुर्घटना और प्राकृतिक आपदाओं के पश्चात 5G कनेक्टिविटी को तुरंत बहाल करने के लिए ड्रोन और बन्धे हुए गुब्बारों का उपयोग करने के नए तरीकों की जांच कर रहा है।
- इस तकनीक का उद्देश्य ऐसी परिस्थितियों में नियमित इंटरनेट सेवाएँ बन्द होने की समस्या का समाधान करना है।
- इस परियोजना की व्यवहार्यता का मूल्यांकन आगामी महीनों में किया जाएगा, तथा अगले वर्ष जून तक निर्णय लिए जाने की सम्भावना है।
- दूरसंचार विभाग के नेतृत्व में किए जाने वाले परीक्षणों में पतंगों और ड्रोन का उपयोग करके वास्तविक दुनिया के परिदृश्यों में अस्थायी 5G नेटवर्क स्थापित करने की व्यवहार्यता का मूल्यांकन किया जाएगा।
- इनका उद्देश्य दूरस्थ दुर्घटना स्थलों और प्राकृतिक आपदाओं जैसी आपातकालीन स्थितियों में मोबाइल सेवा उपलब्ध कराना है।

बीमा क्षेत्र में प्रशासन को बढ़ावा देने के लिये ऑडिट किया अनिवार्य

- भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने भारत में स्वास्थ्य बीमा सेवाओं की प्रभावशीलता और दक्षता में सुधार करने के इरादे से 30 मई, 2024 को एक अत्यधिक महत्वपूर्ण बयान जारी किया।
- इस संशोधन का उद्देश्य पॉलिसीधारकों के लिए कैशलेस क्लेम प्रक्रिया को सरल और तेज करते हुए बीमा कम्पनियों को कड़े प्रतिक्रिया समय का पालन करने के लिए मजबूर करना है।
- नए कानून के अनुसार सभी बीमा कम्पनियों को भुगतान की आवश्यकता के बिना विवादों को हल करने के लिए हर सम्भव प्रयास करना आवश्यकता है।
- इन नियमों का मुख्य उद्देश्य पॉलिसीधारकों के प्रतिदिन के पश्चात प्रतिपूर्ति प्राप्त करने की आवश्यकता को कम करना है।

गृह मन्त्रालय की संचार साथी पहल

- दूरसंचार विभाग और गृह मन्त्रालय ने फर्जी SMS से निपटने के लक्ष्य के साथ 29 मई, 2024 को संचार साथी पहल शुरू की।



- इस कार्यक्रम का उद्देश्य भ्रामक सन्देशों के प्रसार को सम्बोधित करना है जो भोले-भाले मोबाइल उपयोगकर्ताओं को शिकार बनाते हैं।
- विशेष रूप से, धोखेबाजों द्वारा आमतौर पर उपयोग किये जाने वाले 8 SMS हेडर पाए गए हैं, जो सरकार द्वारा ब्लैकलिस्ट किए गए हैं।
- दूरसंचार विभाग ने पिछले 3 महीनों में 8 अलग-अलग स्रोतों से आए करीब 10000 फर्जी मेल पकड़ी हैं।
- दूरसंचार विभाग ने कड़ी कार्रवाई करते हुए इन अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए इन व्यवसायों से जुड़े 1522 SMS कण्टेन्ट टेम्प्लेट और 73 SMS हेडर को ब्लॉक कर दिया है।

CSC के माध्यम से ई-माइग्रेट सेवाएँ

- विदेश मन्त्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मन्त्रालय एवं कॉमन सर्विसेज सेण्टर्स ई-गवर्नेंस सर्विसेज इण्डिया लिमिटेड द्वारा

29 मई, 2024 को सम्पूर्ण देश में ई-माइग्रेट सेवाओं की पेशकश करने की योजना की रूपरेखा तैयार करते हुए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

- ई-माइग्रेट परियोजना के लिए प्राथमिक लक्षित दर्शक ब्लू-कॉलर कार्यकर्ता हैं, जो आवश्यक आत्रजन जांच वाले देशों में प्रवास कर रहे हैं।
- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मन्त्रालय के अनुसार, परियोजना को सुरक्षित और वैध प्रवासन की सुविधा के लिए विदेशी नियोक्ताओं, बीमा कम्पनियों और पंजीकृत भर्ती एजेंटों को एक मंच पर लाने के लिए डिजाइन किया गया था।

MeitY द्वारा राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन

- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मन्त्रालय (MeitY) द्वारा 28 मई, 2024 को 'Powering Transformation through UI/UX for Digital Governance' विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।
- कार्यशाला के दौरान वेबसाइटों, पोर्टलों और अनुप्रयोगों पर उपयोगकर्ताओं के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए सिफारिशें स्थापित की गईं।
- डिजिटल वातावरण तेजी से बदल रहा है, और उपयोगकर्ता सरल, सीधे अनुप्रयोग के साथ बातचीत की आशा करते हैं। इस दिशा में प्रगति करना 'Powering Transformation through UI/UX for Digital Governance' विषय पर इस कार्यशाला का लक्ष्य है।
- जनता को दिखाई देने वाली डिजिटल सेवाओं के लिए एक कुशल UX/UI बनाने में सर्वोत्तम प्रथाओं और बाधाओं का पता लगाने के लिए, कार्यशाला सरकारी, उद्योग, डिजाइनरों, डेवलपर्स और अन्य प्रासंगिक चिकित्सकों के हितधारकों को एक साथ लाती है।

खाद्य एवं पोषण बोर्ड भंग

- कई संगठनों को सुव्यवस्थित करने के सरकार के प्रयास के अन्तर्गत खाद्य और पोषण बोर्ड (FNB) को 27 मई, 2024 को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया।
- महिला और बाल विकास मन्त्रालय (WCD) का खाद्य और पोषण बोर्ड (FNB) एक तकनीकी प्रभाग है जो सामुदायिक पोषण कार्यक्रमों को तार्किक रूप से समर्थन देने का कार्य करता है।
- महिला एवं बाल विकास मन्त्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, FNB, जो फरीदाबाद, मुम्बई, कोलकाता और चेन्नई जैसे प्रमुख शहरों के आसपास 4 क्षेत्रीय कार्यालयों और कई गुणवत्ता नियन्त्रण प्रयोगशालाओं वाले कार्यालयों का एक विशाल नेटवर्क चलाता था, को भंग कर दिया गया था।

अवैध विदेशी कॉलों को रोकने के लिए एक प्रणाली

- दूरसंचार विभाग (DoT) और मोबाइल प्रदाताओं ने 27 मई, 2024 को भारतीय फोन नम्बर प्रदर्शित करने वाली फर्जी अन्तर्राष्ट्रीय कॉल की पहचान करने और उसे रोकने के लिए एक नई तकनीक शुरू की।
- यह कार्रवाई उन लोगों की कई शिकायतों के जवाब में की गई थी, जिन्होंने FedEx कर्मचारी, पुलिस अधिकारी, दूरसंचार विभाग (DoT) के कर्मी, या यहाँ तक कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) के प्रतिनिधि होने का दावा किया था।
- दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार कंपनियों को इस मुद्दे को हल करने के लिए इन फर्जी कॉल को रोकने का निर्देश दिया है।
- परिवर्तित कॉलर लाइन पहचान (CLIs) के साथ ये धोखाधड़ी वाली कॉल भारतीय उपयोगकर्ताओं तक नहीं पहुँच पाती हैं, क्योंकि सिस्टम उन्हें ब्लॉक करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

सामान्य बीमा कंपनियों के लिए संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित

- आयुष मन्त्रालय ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (AIIA) के साथ साझेदारी में, 27 मई, 2024 को नई दिल्ली में AIIA परिसर में एक संवेदीकरण कार्यशाला आयोजित की।
- इस कार्यक्रम में सामान्य बीमा कंपनियों के CEO और CMD के साथ-साथ आयुष अस्पतालों के मालिक भी उपस्थित थे, जिन्होंने बीमा उद्योग और आयुष स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के मध्य सूचना साझा करने की सुविधा प्रदान करने की मांग की।
- इसने साझेदारी को बढ़ावा दिया, जो सम्पूर्ण देश में समग्र स्वास्थ्य और भलाई को आगे बढ़ाता है और आयुष सेवाओं की जनता की पहुँच एवं लागत में सुधार करता है।
- इसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी के पास आयुर्वेदिक दवाओं तक सरल पहुँच हो।
- उद्योग ने पिछले 10 वर्षों में आयुर्वेदिक उत्पाद निर्माण में 8 गुना वृद्धि के साथ असाधारण वृद्धि का अनुभव किया है।

उत्तर प्रदेश है राज्य उपयोगिताओं द्वारा ट्रांसमिशन लाइनों को जोड़ने में शीर्ष राज्य

- केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) द्वारा 26 मई, 2024 को सार्वजनिक किए गए आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश ने वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान राज्य ट्रांसमिशन उपयोगिताओं द्वारा जोड़ी गई ट्रांसमिशन लाइनों की संख्या के मामले में अन्य सभी राज्यों को पीछे छोड़ दिया है।

- FY24 में, 'राज्य उपयोगिता उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड' (UPPTCL) द्वारा 220kV या उससे अधिक की 1460 ckm ट्रांसमिशन लाइनें जोड़ी गई।
- यह अन्य सभी राज्य उपयोगिताओं की उपलब्धियों से बहुत अधिक है।
- FY24 के अन्त तक, दूसरे स्थान पर रहने वाली उपयोगिता, गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (GETCO) ने 898 ckm जोड़ा था।
- राज्य विद्युत प्रदाताओं ने FY24 में कुल 6993 ckm ट्रांसमिशन लाइनें जोड़ीं, जो 11002 ckm लक्ष्य का लगभग 64% है। UPPTCL का राज्य क्षेत्र की कुल वृद्धि में 20% से थोड़ा अधिक योगदान है।

राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए पोर्टल नामांकन

- शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार (उच्च शिक्षा) 2024 नामांकन पोर्टल, 21 मई, 2024 को उच्च शिक्षा सचिव संजय मूर्ति द्वारा खोला गया।
- पॉलिटैक्निक संस्थानों और तकनीकी और गैर-तकनीकी उच्च शिक्षा संस्थानों के शिक्षकों को सम्मान मिलेगा।
- शिक्षा मन्त्रालय के अनुसार, चुने गए प्राप्तकर्ताओं को पूर्व राष्ट्रपति डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के सम्मान में 5 सितम्बर, शिक्षक दिवस पर सम्मानित किया जाएगा।
- कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, पॉलिटैक्निक और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों में सभी संकाय सदस्य इस सम्मान को प्राप्त करने के पात्र हैं।
- मन्त्रालय के अनुसार, नामांकित व्यक्ति के पास कम-से-कम 5 वर्ष का पूर्णकालिक स्नातक और स्नातक शिक्षण अनुभव होना चाहिए। नामांकन जमा करने की अन्तिम तिथि 20 जून है।

इंडियास्किल्स कम्पटीशन 2024 आयोजित

- देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता, द इण्डियास्किल्स कम्पटीशन 2024, जिसका उद्देश्य स्किलिंग के उच्चतम मानकों को प्रदर्शित करना है, 15 मई, 2024 को शुरू हुई।



- यशोभूमि, द्वारका, नई दिल्ली में आयोजित एक उद्घाटन समारोह में, कौशल विकास और उद्यमिता मन्त्रालय (MSDE) 30 से अधिक राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के 900 से अधिक छात्रों के साथ-साथ 400 से अधिक उद्योग विशेषज्ञों की उम्मीद कर रहा है।
- 4 दिवसीय इण्डिया स्किल्स इवेंट के माध्यम से, प्रतिभागी पारम्परिक शिल्प से लेकर अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों तक 61 प्रतिभाओं के साथ एक राष्ट्रीय मंच पर अपनी व्यापक क्षमताओं और प्रतिभा का प्रदर्शन करने में सक्षम होंगे।
- उपलब्ध सर्वोत्तम बुनियादी ढांचे को ध्यान में रखते हुए ऑनसाइट आयोजित की जाने वाली 47 कौशल प्रतियोगिताएं अतिरिक्त, गुजरात, कर्नाटक, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 14 कौशल प्रतियोगिताएं ऑकसाइट आयोजित की जाएंगी।

प्रसार भारती परिवार-अनुकूल OTT प्लेटफॉर्म करेगा लॉन्च

- भारत सरकार द्वारा संचालित ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती ने 15 मई, 2024 को अगस्त, 2024 तक अपनी स्वयं की ओवर-द-टॉप स्ट्रीमिंग सेवाएं शुरू करने की योजना बनाई है।
- यह सेवा परिवार-अनुकूल सामग्री प्रदान करेगी, जो भारतीय समाज और संस्कृति को दर्शाती है।
- यह परियोजना सामग्री से सम्बन्धित उन मुद्दों का सीधा जवाब है, जो उपभोगकर्ताओं को हॉटस्टार और नेटफ्लिक्स जैसे प्रीमियम OTT प्रदाताओं पर मौजूद लगते हैं।
- OTT प्लेटफॉर्म को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार द्वारा 100-दिवसीय योजना में जोड़ा गया है, लेकिन केवल तभी जब वह लगातार तीसरा कार्यालय सुरक्षित कर ले।
- मार्च में, सूचना और प्रसारण मन्त्रालय द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 का उपयोग 'अश्लील और अपमानजनक' सामग्री प्रदर्शित करने के लिए 18 ओवर-द-टॉप (OTT) प्लेटफॉर्मों को बन्द करने के लिए किया गया था।

6.80 लाख मोबाइल कनेक्शन अवैध घोषित

दूरसंचार विभाग ने 23 मई, 2024 को लगभग 6.80 लाख मोबाइल कनेक्शनों को अवैध और धोखाधड़ी वाला घोषित कर दिया। ऑपरेटरों को इन चिन्हित मोबाइल नम्बरों को अभी फिर से सत्यापित करने का निर्देश दिया गया है।

सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लिए यह आवश्यक है कि वे 60 दिनों के भीतर पहचान किए गए कनेक्शनों की पुनः जाँच करें। इसमें कहा गया है कि अगर दोबारा सत्यापन पूरा नहीं हुआ, तो प्रभावित मोबाइल नम्बर काट दिए जाएंगे।

CAA के अन्तर्गत नागरिकता प्रमाण-पत्र का पहला सेट जारी

- नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 के प्रकाशन के पश्चात, नागरिकता प्रमाण-पत्रों का पहला बैच 15 मई, 2024 को जारी किया गया।
- नई दिल्ली में केन्द्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने 14 उम्मीदवारों को नागरिकता प्रमाण-पत्र प्रदान किए।
- गृह मन्त्रालय के अनुसार, कई और उम्मीदवारों को कथित तौर पर ईमेल के माध्यम से डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र प्राप्त हो रहे हैं।
- आवेदकों को बधाई देने के अतिरिक्त, गृह सचिव ने नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 के प्रमुख प्रावधानों को रेखांकित किया, जो 11 मार्च, 2024 को प्रकाशित हुए थे।
- नियमों के अनुसार, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में हिन्दू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समूहों के व्यक्ति, जिन्होंने 31 दिसम्बर, 2014 से पहले भारत में प्रवेश किया था, वे आवेदन करने के पात्र थे।

वकीलों को उपभोक्ता अधिनियम दायित्व से छूट

- सुप्रीम कोर्ट द्वारा 14 मई, 2024 को जारी एक ऐतिहासिक निर्णय, वकीलों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत दायित्व से छूट देता है।
- राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) ने पहले वर्ष 2007 में फैसला सुनाया था कि अधिनियम के अन्तर्गत कानूनी सेवाएं दोषपूर्ण हैं।
- न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने इस बात पर बल दिया कि भुगतान किये जाने के बावजूद, कानूनी प्रतिनिधित्व अपने विशिष्ट पेशेवर गुणों के कारण उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम द्वारा परिभाषित 'सेवा' के रूप में योग्य नहीं है।
- CPA के अन्तर्गत, न्यायालय ने पेशेवरों और अन्य कम्पनी प्रकारों के मध्य एक स्पष्ट विभाजन किया।
- उन्होंने इस बात पर बल दिया कि जब CPA पहली बार पारित किया गया था और बाद में इसमें संशोधित किया गया था, तब कोई सबूत नहीं था कि इसका मतलब वकीलों या डॉक्टरों द्वारा दी जाने वाली पेशेवर सेवाओं को शामिल करना था।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अरावली में खनन के नए पट्टे देने पर रोक

- सर्वोच्च न्यायालय ने 10 मई, 2024 को 4 राज्यों को अरावली में नए खनन पट्टे देने से प्रतिबंधित कर दिया।

- 4 राज्य जहाँ अरावली लोग रहते हैं- दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात- न्यायालय के फैसले के दायरे में आते हैं।
- केन्द्रीय अधिकार प्राप्त समिति (CEC) के अध्ययन में कहा गया है कि अरावली में पहाड़ियाँ हैं और पहाड़ियों के चारों ओर एक सुसंगत बफर जोन है, जो 100 मी चौड़ा है।
- न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि उसके फैसले को उन खनन कार्यों पर प्रतिबन्ध के रूप में नहीं माना जाएगा, जो वर्तमान में वैध परमिट और लाइसेंस के अंतर्गत सीमा के भीतर चल रहे हैं।
- यह पारिस्थितिकी तन्त्र की रक्षा और खनन में शामिल व्यक्तियों के लिए आजीविका के साधन बनाए रखने के मध्य सन्तुलन बनाए रखने के लिए किया गया था।

'रन फॉर सन' मैराथन का आयोजन

- भारत सरकार ने सम्पूर्ण विश्व के साथ 3 मई, 2024 को इंटरनेशनल सन डे मनाया, जो एक हरित और स्वस्थ ग्रह को बढ़ावा देने में सौर ऊर्जा के प्रमुख लाभों का एक वार्षिक अनुस्मारक है।



- नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने इस दिन 'रन फॉर सन' मैराथन की मेजबानी की।
- 'रन फॉर सन' मैराथन का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन को कम करने और सभी के लिए एक स्वच्छ, स्वस्थ भविष्य को आगे बढ़ाने में सौर ऊर्जा की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना है।

भारतीय ऐतिहासिक रिकॉर्ड आयोग के लिए नया प्रतीक और लोगो

- भारतीय ऐतिहासिक रिकॉर्ड आयोग ने 25 अप्रैल, 2024 को एक नया प्रतीक और उद्देश्य अपनाया।
- वर्ष 1919 में स्थापित IHRC का नेतृत्व केन्द्रीय संस्कृति मन्त्री करते हैं। यह प्रतीक IHRC की थीम और मौलिकता को सम्पूर्ण रूप से दर्शाता है।
- कमल की पंखुड़ियों के आकार वाले पृष्ठ, IHRC को ऐतिहासिक दस्तावेजों को संरक्षित के लिए एक दृढ़ नोडल संगठन के रूप में दर्शाते हैं। मध्य में सारनाथ स्तम्भ भारत की समृद्ध विरासत का प्रतीक है।

NSDC और ISKCON का जनजातीय कौशल विकास के लिए सहयोग

- ISKCON और NSDC भारत में आदिवासी और गरीब युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए मिलकर कार्य करेंगे।
- साझेदारी का प्रारंभिक केन्द्र उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश पर होगा, जिसका उद्देश्य वंचित लोगों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना है।
- इस रणनीतिक समझौते के अन्तर्गत अल्पकालिक पाठ्यक्रम पेश किए जाएंगे, जो स्किल इण्डिया डिजिटल हब प्लेटफॉर्म के माध्यम से उद्योग-मान्यता प्राप्त क्रेडेन्शियल्स प्रदान करेंगे।
- इसका उद्देश्य रोजगार में सुधार करना और सिखाए गए व्यक्तियों को नए इंटरनेशनल के माध्यम से घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय कार्य संभावनाओं तक पहुँच प्रदान करना है।

शोम्पेन जनजाति ने चुनाव में पहली बार किया मतदान

- भारत के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) में से एक, शोम्पेन जनजाति ने 23 अप्रैल, 2024 को अण्डमान और निकोबार लोकसभा सीट पर मतदान किया, इस प्रकार उन्होंने पहली बार अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया।
- वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, शोम्पेन जनजाति के लगभग 229 लोग हैं।
- अण्डमान और निकोबार लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र ने कुल 63.99% मतदान हासिल किया, जो वर्ष 2019 के चुनावों में हुए 65.09% मतदान से मामूली कम था।
- चुनाव प्रक्रिया में शोम्पेन जनजाति की भागीदारी बेहद महत्वपूर्ण है।

आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में भारत का प्रगतिशील मार्ग

- विधि एवं न्याय मंत्रालय के कानूनी मामलों के विभाग ने 21 अप्रैल, 2024 को एक सम्मेलन की मेजबानी की।
- यह नई दिल्ली के जनपथ स्थित डॉ अम्बेडकर इंटरनेशनल सेण्टर में 'आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ' विषय पर हुआ। सम्मेलन की पृष्ठभूमि 3 आपराधिक कानूनों का अधिनियमन थी, जो 1 जुलाई, 2024 से लागू होंगे।
- इन कानूनों को भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 कहा जाता है।
- भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे।

LGBTQ कल्याण के लिए समिति नियुक्त

- केन्द्र सरकार ने 20 अप्रैल, 2024 को LGBTQ सामुदायिक कल्याण के लिये एक समिति की स्थापना की।
- महत्वपूर्ण मन्त्रालयों के सचिवों सहित समूह के 6 सदस्यों का नेतृत्व केन्द्रीय गृह सचिव राजीव गोबा करेंगे।
- समिति का मुख्य लक्ष्य उन नीतियों के लिए सिफारिशें करना है जो विभिन्न सन्दर्भों में LGBTQ+ व्यक्तियों के विरुद्ध भेदभाव को समाप्त करेंगी।
- इसमें जबरन चिकित्सा प्रक्रियाओं या उपचारों को समाप्त करना, सुरक्षा सावधानियों में सुधार करना, उत्पादों एवं सेवाओं तक समान पहुँच की गारंटी देना, और सामाजिक कल्याण लाभों में असमानताओं को हल करना शामिल है।

विदेशी प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत संशोधन नियम अधिसूचित

- अन्तरिक्ष क्षेत्र के लिये 100% FDI तक की अनुमति देने के अपने निर्णय को क्रियान्वित करने के लिये सरकार ने 18 अप्रैल, 2024 को विदेशी मुद्रा प्रबन्धन अधिनियम के अन्तर्गत नए दिशानिर्देश जारी किये।
- उपग्रहों का उत्पादन और संचालन, उपग्रह डेटा उत्पाद, ग्राउण्ड सेगमेंट और उपयोगकर्ता सेगमेंट सभी 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए पात्र हैं।
- जिसमें 74% से अधिक निवेश के लिए सरकार की अनुमति की आवश्यकता होगी।
- कुल निवेश का 74% तक स्वचालित विधि के माध्यम से जाएगा।
- अंतरिक्ष यान लैण्डिंग और टेकऑफ के लिए स्पेसपोर्ट के विकास के साथ-साथ लॉन्च वाहनों और सम्बन्धित प्रणालियों या उप-प्रणालियों के लिए स्वचालित FDI के माध्यम से 49% तक धन भी उपलब्ध कराया गया है।

राष्ट्रीय प्रसारण नीति के निर्माण पर परामर्श पत्र जारी

- भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) द्वारा 2 अप्रैल, 2024 को राष्ट्रीय प्रसारण नीति-2024 के निर्माण के सुझावों पर एक परामर्श पत्र जारी किया गया।
- नीति-निर्माण प्रक्रिया में उपयोग किए गए इनपुट का उद्देश्य रणनीतिक विस्तार और उन्नति के लिए लक्ष्यों, योजनाओं एवं रणनीतियों को परिभाषित करना है।

- इस परामर्श पत्र में भारत को विषय-वस्तु के लिए एक वैश्विक केन्द्र के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से उन महत्वपूर्ण सरोकारों की पहचान की गई है, जो सामान्यतः प्रसारण उद्योग में विद्यमान हैं।
- दस्तावेज सार्वजनिक सेवा प्रसारण में सुधार करने, विभिन्न मीडिया और मनोरंजन क्षेत्रों के साथ समस्याओं से निपटने, पायरेसी को रोकने और सामग्री सुरक्षा की गारंटी देने के तरीके को सम्बोधित करता है।

‘वन व्हीकल, वन फास्टैग’ लागू

- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा 1 अप्रैल, 2024 को ‘वन व्हीकल, वन फास्टैग’ मानक लागू किया गया।
- इसका लक्ष्य लोगों के कई फास्टैग्स को एक साथ जोड़ने या कई कारों के लिए एक फास्टैग (FASTag) का उपयोग करने से रोकना है।
- NHAI ने पेटीएम फास्टैग उपयोगकर्ताओं को होने वाली समस्याओं को देखते हुए पहले ही अनुपालन की समय सीमा मार्च के अन्त तक बढ़ा दी थी।
- ‘वन व्हीकल, वन फास्टैग’ अभियान का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली की प्रभावशीलता में सुधार करना और टोल प्लाजा पर सुचारू यातायात की गारंटी देना है।
- NHAI भारत में इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली फास्टैग चलाता है। यह सम्बन्धित बचत या प्रीपेड खाते से सीधे टोल भुगतान करने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) तकनीक का लाभ उठाता है।

USB चार्जर घोटाले को लेकर केन्द्र की चेतावनी

- केन्द्र सरकार ने 1 अप्रैल, 2024 को लोगों को बस स्टॉप, कॉफी शॉप, होटल और हवाई अड्डों सहित सार्वजनिक स्थानों पर फोन चार्जिंग पोर्टल का उपयोग नहीं करने की सलाह दी है।

- USB चार्जिंग पोर्टल अक्सर साइबर अपराधियों द्वारा सार्वजनिक स्थानों जैसे बस स्टॉप, होटल, कैफे और हवाई अड्डों में दुर्भावनापूर्ण रूप से उपयोग किए जाते हैं।
- असुरक्षित USB स्टेशनों पर अपने उपकरणों को चार्ज करने वाले उपयोगकर्ता साइबर हमले के शिकार हो सकते हैं, जिसे ‘जूस-जैकिंग’ कहा जाता है।
- एक सामान्य साइबर हमले की रणनीति जिसे ‘जूस जैकिंग’ के रूप में जाना जाता है, में साइबर अपराधी सार्वजनिक USB चार्जिंग स्टेशनों का उपयोग करके या तो उपयोगकर्ता डेटा चुराते हैं या जुड़े उपकरणों को मैलवेयर से संक्रमित करते हैं।

सम्पूर्ण भारत के उत्पादों को GI टैग अर्जित

- प्रसिद्ध बनारस ठण्डाई सहित पूरे भारत के 60 से अधिक उत्पादों पर 1 अप्रैल, 2024 को भौगोलिक संकेत (GI) लेबल को लागू किया गया है।
- यह पहली बार है जब एक साथ इतनी मात्रा में GI टैग दिए गए हैं।
- राज्य आगे बढ़कर अपने कुछ ऐतिहासिक और पारम्परिक उत्पादों को GI टैग सौंपने के लिए आवेदन-पत्र जमा कर रहे हैं।
- बिहू ढोल, पानी मेटेका शिल्प, जापी, मिशिंग हथकरघा उत्पाद और अशरीकण्डी टेराकोटा कालीन सभी असम से हैं।
- बनारसी ठण्डाई, बनारसी तबला, शहनाई, बनारसी लाल भरवामिर्च और बनारसी लाल पेड़ा ये सभी वाराणसी से हैं।
- माताबारी पेड़ा और पचरा रिगनाई त्रिपुरा क्षेत्र की 2 वस्तुएँ हैं, जिन्हें GI टैग से सम्मानित किया गया है।
- मेघालय राज्य से चुबिची, मेघालय गारो टेक्सटाइल और मेघालय लिर्नाई पॉटरी को GI टैग हुआ।



चुनाव आयोग द्वारा ‘मिथक बनाम वास्तविकता रजिस्टर’ लॉन्च

वर्ष 2024 में आम चुनावों से पहले झूठी सूचनाओं को फैलने से रोकने के प्रयास में, चुनाव आयोग ने 2 अप्रैल, 2024 को ‘मिथक बनाम वास्तविकता’ रजिस्टर लॉन्च किया। यह रजिस्टर चुनाव के बारे में पहले से ही उजागर गलत जानकारी, सम्भावित झूठ, महत्वपूर्ण विषयों पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, और प्रत्येक पार्टी के लिए श्रेणियों में विभाजित सन्दर्भ संसाधन प्रदान करता है। रजिस्टर में नियमित अपडेट किया जाएगा। चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट इसे सार्वजनिक पहुँच प्रदान करेगी।

ग्रेट इण्डियन बस्टर्ड संरक्षण के लिए समिति नियुक्त

- सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चन्द्रचूड ने 26 मार्च, 2024 को ग्रेट इण्डियन बस्टर्ड के गम्भीर खतरे से निपटने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की। जिसमें संरक्षण को संतुलित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है।
- गुजरात और राजस्थान में, शक्तिशाली विद्युत तारों के साथ टकराव से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की आबादी विलुप्त हो सकती है।
- सुप्रीम कोर्ट ने पक्षियों की प्रजातियों की सुरक्षा के लिए भूमिगत विद्युत तारों के अपने आदेश पर पुनर्विचार किया है।
- समिति वन्यजीव, विशेषज्ञ, पर्यावरणविद और सम्बन्धित विभागों के सरकारी अधिकारी शामिल हैं।

सुलभ मतदान के लिए पहल का शुभारम्भ

- भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने 25 मार्च, 2024 को वृद्ध मतदाताओं और दिव्यांगजनों पर बल देने के लिए एक पहल का शुभारम्भ किया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मतदान सभी भारतीयों के लिए सुलभ है।
- ECI का आदर्श वाक्य 'नो वोट इज लेफ्ट बिहाइण्ड,' सुलभ और समावेशी चुनावों के लिए उसके समर्पण को प्रदर्शित करता है।
- 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता और 40% बेसलाइन विकलांगता वाले दिव्यांगजन सक्षम ऐप की मदद से घर से ही मतदान कर सकते हैं।

सरकार के विरुद्ध फर्जी खबरों की पहचान करने के लिए एक फैक्ट-चेकिंग यूनिट

- केन्द्र सरकार ने 20 मार्च, 2024 को सोशल मीडिया पर सरकार के विरुद्ध किसी भी फर्जी खबर पर नजर रखने के लिए फैक्ट-चेकिंग टीम की स्थापना की घोषणा की।
- यह घोषणा बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा कॉमेडियन कुणाल कामरा के FCU की स्थापना को रोकने के अस्थायी अनुरोध को अस्वीकार करने के कुछ दिनों बाद की गई थी।
- IT नियमों के अनुसार, FCU को किसी भी पोस्ट के सोशल मीडिया मध्यस्थों को सूचित करना आवश्यक है जो भ्रामक हैं।
- यह धोखाधड़ी, गलत या सरकारी कार्यों से सम्बन्धित भ्रामक जानकारी के बारे में भी रिपोर्ट करेगा।

सट्टेबाजी और जुआ प्लेटफार्मों के लिए दिशानिर्देश जारी

- सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 21 मार्च, 2024 को सोशल मीडिया प्रभावितों को चेतावनी के साथ ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी प्लेटफार्मों के लिए दिशा निर्देश जारी किए।



- इण्टरनेट सट्टेबाजी और गेमिंग के पर्याप्त वित्तीय और सामाजिक आर्थिक प्रभावों को देखते हुए उपभोक्ताओं, विशेषकर युवाओं के लिए मन्त्रालय ने सलाह जारी की।
- यह अनुशंसा की जाती है कि इण्टरनेट विज्ञापन बिचौलिए भारतीय दर्शकों को ऐसी सामग्री को लक्षित करने से बचें।
- इसके अतिरिक्त, सोशल मीडिया मध्यस्थों को अपने उपयोगकर्ताओं को ऐसी सामग्री प्रकाशित करने के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए कार्य करना चाहिए।

मानव तस्करी से निपटेंगे राष्ट्रीय महिला आयोग और RPF

- राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) और रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने मानव तस्करी से निपटने और उसे रोकने के लिए 19 मार्च, 2024 को नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- रेलवे स्टेशनों पर तैनात रेल सुरक्षा बल के जवान महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
- मानव तस्करी के 70% मामले बच्चियों और महिलाओं के हैं।
- इस समझौता ज्ञापन का समग्र उद्देश्य महिलाओं को एक सुरक्षित यात्रा अनुभव प्रदान करना है।
- RPF यह सुनिश्चित करेगा कि रेलवे नेटवर्क पर मानव तस्करी सहित महिलाओं के विरुद्ध कोई अपराध न होने दिया जाए

महिला स्वयं सहायता समूह को 1000 ड्रोन वितरित

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 17 मार्च, 2024 को समुदायों में महिलाओं को कृषि ड्रोन वितरित किए, यह उस सामाजिक मानदण्ड को चुनौती देने के प्रयास में है, जो महिलाओं को ट्रैक्टर चलाने से भी रोकता है।

- ग्रामीण क्षेत्रों में महिला स्वयं-सहायता समूहों को नमो ड्रोन दीदी योजना के अन्तर्गत 1000 ड्रोन वितरित किए जाएंगे।
- सरकार विशेष रूप से महिलाओं को इन भूमिकाओं को संभालने के लिए चुन रही है, ताकि उन्हें अधिक आर्थिक और तकनीकी अधिकार दिए जा सकें।
- इन ड्रोनों से समुदायों में कृषि और महिलाओं का भविष्य बदल जाएगा।

18 OTT प्लेटफार्मों पर प्रतिबन्ध

- भारत सरकार ने 16 मार्च, 2024 को आपत्तिजनक जानकारी प्रदर्शित करने के लिए 18 ओवर-द-टॉप (OTT) साइटों पर प्रतिबन्ध लगा दिया।
- कानूनी उल्लंघनों का हवाला देते हुए, सूचना और प्रसारण मन्त्रालय ने इन प्लेटफार्मों के साथ-साथ वेबसाइटों, मोबाइल एप्लिकेशन और सोशल मीडिया खातों तक पहुंच को प्रतिबन्धित कर दिया है।
- मन्त्रालय ने इन 18 प्लेटफॉर्मों के अतिरिक्त इन सेवाओं से जुड़ी 19 वेबसाइटों, 10 एप्लिकेशंस और 57 सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को ब्लॉक कर दिया है।
- भारत के तेजी से बढ़ते स्ट्रीमिंग बाजार को नियंत्रित करने के सरकार के बड़े प्रयासों में 18 OTT प्लेटफार्मों पर हमला शामिल है।

मोटर वाहन दुर्घटना पीड़ितों के कैशलेस उपचार के लिए प्रायोगिक कार्यक्रम

- केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मन्त्रालय ने 16 मार्च, 2024 को धन की आवश्यकता के बिना यातायात दुर्घटनाओं के पीड़ितों के उपचार के लिए एक प्रायोगिक परियोजना की शुरुआत करने की घोषणा की।
- यह योजना सबसे पहले चण्डीगढ़ में शुरू की जाएगी, इसका उद्देश्य यह गारण्टी देना है कि दुर्घटना पीड़ितों को समय पर चिकित्सा सहायता मिले विशेष रूप से महत्वपूर्ण गोल्डन ऑवर्स (स्वर्णिम समय) में।
- केन्द्रशासित प्रदेश में यातायात दुर्घटनाओं के सभी पीड़ित दुर्घटना की तिथि से अधिकतम 7 दिनों की अवधि के लिए प्रति व्यक्ति ₹ 1.5 लाख तक कैशलेस के लिए पात्र होंगे।
- मोटर वाहन से जुड़े किसी भी प्रकार की यातायात दुर्घटना को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कवर किया जाएगा।

'इथेनॉल 100' ईंधन पहल प्रस्तुत

- पेट्रोलियम मन्त्री हरदीप सिंह पुरी ने 15 मार्च, 2024 को उत्सर्जन कम करने और स्थिरता को